विचार बिन्दु

सब लोग दाता नहीं तो कम से कम उदार तो बन ही सकते हैं। –अफलातून

राजस्थान दिवस का उत्सवी आयोजन :

जनोन्मुखी सोच से होगा खुशहाल राज्य का सपना साकार

एक जन कल्याणकारी सरकार का यह प्राथमिक कर्तव्य और दायित्व है कि आम जन से कदम से कदम मिलाकर रोजमर्रा के कार्यों के लिए सरकार और जन साधारण के बीच आपसी संवाद को और आसान कैसे बनाया जाये, इसके लिए अधिक तत्परता व सजगता से काम करना होगा। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सुशासन के महत्वपूर्ण स्तम्भ हैं। इन मूलभूत सुविधाओं को आसानी से बिना विघ्न बाधा के सभी को सुलभ करने के लिए सरकार और जन प्रतिनिधियों को एक जुट होकर प्रयास करने की जरुरत है तभी राजस्थान दिवस के उत्सवी कार्यक्रमों से हमाराखुशहाल राज्य का सपना साकार होगा।

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल 25 मार्च से राजस्थान दिवस के साप्ताहिक कार्यक्रमों के जरिये जनसेवा की अपनी सोच को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश के सामाजिक, आर्थिक विकास, समाज के कमजोर और पिछड़े वर्ग के कल्याण और आधारभूत ढांचे को जन आंकाक्षाओं के अनुरूप मजबूत बनाने में जुटे हैं। राज्य की डबल इंजन सरकार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की भावना के अनुरूप एक खुशहाल, शिक्षित, संवेदनशील और समृद्ध राजस्थान के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। मुख्य मंत्री का मानना है, जब समाज के सभी वर्ग सौहार्दपूर्वक इस दिशा मैं प्रयासरत होंगे तभी हम एक सशक्त राजस्थान का नवनिर्माण कर पाएंगे। हम सुनिश्चित करते हैं कि समाज के सभी वर्गों के साथ बेहतर तालमेल के साथ कार्य हो। राजस्थान स्थापना दिवस के कार्यक्रम प्रदेशभर में गरिमा के साथ आयोजित किये जा रहे है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की सोच और मंशा के अनुरूप 25 मार्च से आयोजित हो रहे राजस्थान दिवस महोत्सव के कार्यक्रमों में जनभागीदारी देखी जा रही है। मुख्यमंत्री का कहना है कार्यक्रमों की संख्या नहीं गुणवत्ता एवं गरिमा के साथ आयोजन पर ध्यान दिया जाए। राजस्थान दिवस समारोह का साप्ताहिक आगाज 25 मार्च को मरूधरा बाड़मेर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में आयोजित मातृवन्दन को समर्पित 'महिला सम्मेलन' से हुआ। इस अवसर पर 5 हजार महिलाओं को इंडेक्शन कुक टॉप का वितरण किया गया। साथ ही स्वामी विवेकानन्द स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के अंतर्गत 164 छात्राओं को चयन पत्र का वितरण किया। गार्गी पुरस्कार, बालिका प्रोत्साहन एवं मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना के अन्तर्गत 31 हजार 790 बालिकाओं को 13.16 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की। राजकीय महाविद्यालयों के पुस्तकालयों में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। इसी क्रम में हमने आज विभिन्न जिलों के 36 महिला महाविद्यालयों में ये सुविधा प्रारंभ की है। वर्ष 2025–26 के बजट में वंचित वर्गों, महिलाओं, बुजुर्गों एवं दिव्यांगों के लिए संचालित आवासीय संस्थानों का मैस भत्ता बढ़ाकर 3 हजार 250 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। सभी संभागीय मुख्यालयों पर 50 बेड के सरस्वती हाफ वे होम्स के माध्यम से बालिका गृहों में निवास करने वाली बालिकाओं के 18 वर्ष की होने के बाद भी उन्हें हैंड होल्डिंग की जरूरत होने पर सुविधा भी दी जाएगी। इसी तरह नारी उत्थान के लिए प्रदेश में 10 जिला मुख्यालयों पर बालिका देखभाल संस्थान की स्थापना, नवगठित नगरीय निकायों सहित अन्य क्षेत्रों में महिलाओं हेतु 500 पिंक टॉयलेट का निर्माण, हर ब्लॉक पर रानी लक्ष्मी बाई केंद्र की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। सोलर दीदी के रूप में नया कैडर बनाकर आगामी वर्ष पहले चरण में स्वयं सहायता समूह की 25 हजार महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। साथ ही, राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को अंतिम 5 महीनों में अतिरिक्त पोषण के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्रीकिट योजना प्रारंभ की जा रही है।

> **राज्य की डबल इंजन सरकार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की भावना के अनुरूप एक खुशहाल, शिक्षित, संवेदनशील और समृद्ध राजस्थान के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। मुख्य मंत्री का मानना है, जब समाज के सभी वर्ग सौहार्दपूर्वक इस दिशा मैं प्रयासरत होंगे तभी हम एक सशक्त राजस्थान का नवनिर्माण कर पाएंगे। हम सुनिश्चित करते हैं कि समाज के सभी वर्गों के साथ बेहतर तालमेल के साथ कार्य हो।**

राजस्थान दिवस उत्सव के दूसरे दिन 26 मार्च को बीकानेर में किसान सम्मेलन एवं किसान उत्पादक संगठन कार्यक्रम के मुख्य समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 30 हजार किसानों को 137 करोड़ रुपये का अनुदान हस्तान्तरण किया गया। साथ ही, इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि राशि में वृद्धि एवं मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के दिशा–निर्देश जारी किए गए। इसके अलावा मंगला पशु बीमा योजना में लाभान्वितों का दायरा भी बढ़ाया गया है। कार्यक्रम में पशुधन नि:शुल्क आरोग्य योजना के अन्तर्गत नि:शुल्क उपलब्ध करवाये जा रहे औषधियों व टीकों की संख्या बढाकर200 किए जाने तथा कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के विभिन्न दिशा–निर्देश जारी किए गए। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बैल से खेती करवाये जाने पर 30 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि के दिशा–निर्देश जारी किए गए। पीएमएफएमई योजना के तीन एफपीओ को अनुदान के तथा एक एफपीओ को शेयर मनी के चैक वितरण किए गए। मुख्यमंत्री का कहना है यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं। केन्द्र सरकार द्वारा 10 हजार एफपीओ का गठन किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य में 72 लाख से अधिक किसानों को 1 हजार 400 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित, लगभग 47 लाख किसानों को 29 हजार करोड़ रुपये का अल्पकालीन ब्याजमुक्त फसली ऋण तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 3 हजार करोड़ रुपये से अधिक के बीमा क्लेम वितरित किए गए हैं। राज्य सरकार के लिए किसान हित पहली प्राथमिकता है। राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले ही वर्ष में किसान सम्मान निधि में सहायता राशि को 6 हजार रूपये से बढ़ाकर 8 हजार किया, जिसे अब बढ़ाकर 9 हजार रूपये कर दिया गया है। इसी भांति मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत 20 लाख से अधिक पशुओं का पंजीकरण, पशुधन नि:शुल्क आरोग्य योजना के तहत नि:शुल्क औषधियां और टीके उपलब्ध कराना, मोबाइल वेटनरी सेवा नंबर 1962 प्रारंभ करने, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना के तहत लगभग 34 हजार पात्र गोपालकों के ऋण स्वीकृति सहित विभिन्न निर्णयों से पशुपालकों को राहत दी जा रही है।

राजस्थान दिवस महोत्सव के तीसरे दिन गुरुवार को भरतपुर में आयोजित अन्त्योदय कल्याण कार्यक्रम के दौरान डीबीटी के माध्यम से 92 हजार से अधिक निर्माण श्रमिकों को 100 करोड़ रुपये की राशि का हस्तांतरण किया गया। साथ ही, डांग, मगरा एवं मेवात क्षेत्रीय विकास योजनाओं के लिए 300 करोड़ रुपये (प्रति योजना 100 करोड़ रूपए) की राशि आवंटित की गई । कार्यक्रम में प्रदेशभर में स्वामित्व कार्ड योजना के तहत 20 हजार पट्टों का वितरण, 311 लोगों को डेयरी बूथ अलॉटमेंट, माटी कलाकारों को विद्युत चालित चाक का वितरण भी किया गया। दिव्यांगजनों को पावर ड्रिवन व्हील चेयर एवं असिस्टिव डिवाइस वितरित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना', गुरू गोलवलकर आशान्वित ब्लॉक विकास योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना की मार्गदर्शिकाओं एवं दिव्यांगजनों के लिए 'समान अवसर नीति 2025' का विमोचन भी किया। साथ ही, दादूदयाल घुमन्तू सशक्तीकरण योजना', मा (MAA) नेत्र वाउचर योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAA) के नूप पैकेज व विधायक जनसुनवाई केंद्र स्थापित किए जाने के संबंध में भी दिशा–निर्देश जारी किए। ग्रामीण विकास के ई–वर्क पोर्टल 2.0 एवं मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया। राजस्थान दिवस सप्ताह के चौथे दिन शुक्रवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भीलवाड़ा में विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण योजनाओं के दिशा–निर्देश जारी करने के साथ ही 10 हजार करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इसके अलावा, राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ करने के साथ सभी जिलों की पंच गौरव पुस्तिका का विमोचन किया तथा ई उपचार एप और राजस्थान सम्पर्क 2.0 पोर्टल का शुभारंभ भी किया।

–अतिथि संपादक,
बालमुकुन्द ओझा,
वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार

राजस्थान दिवस – आत्मावलोकन का अवसर

राजेन्द्र भाणावत

15 अगस्त 1947 को जब देश को स्वतंत्रता मिली, उस समय देश लगभग 500 छोटी–बड़ी रियासतों में बंटा हुआ था। सरदार वल्लभभाई पटेल के प्रयासों से अलग–अलग रियासतों को भारत में विलय करने का कठिन कार्य किया गया। राजस्थान में भी बाईस रियासतें थीं जिनका एक–एक करके भारत में विलय किया गया। राजस्थान प्रदेश 1947 को ही अस्तित्व में आ गया हो, ऐसी बात नहीं है।

1947 से पूर्व राजस्थान, राजपूताना के नाम से जाना जाता था। जिन रियासतों को मिलाकर राजस्थान बना, उनकी संख्या 22 थी जिनमें टोंक को छोड़ कर सबमें हिन्दू राजाओं का राज था। टोंक रियासत में नवाब का शासन था। ब्रिटिश शासन से सीधे संचालित अजमेर मेरवाड़ा भी राजस्थान का भाग बना।

राजस्थान को वर्तमान स्वरूप में आने से पहले निम्न चरणों से गुजरना पड़ा:–

पहला, 1948 को अलवर,भरतपुर, धौलपुर और करौली को मिलाकर मत्स्य संघ बनाया गया। दूसरे चरण में राजस्थान संघ का गठन हुआ जिसमें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर की रियासतों को सम्मिलित किया गया। तीसरे चरण में उदयपुर का विलय होने के पश्चात संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ। चौथे चरण में जयपुर, जोधपुर जैसलमेर और बीकानेर को मिलाकर वृहद राजस्थान का गठन हुआ। यह प्रक्रिया 30 मार्च 1949 को पूरी हुई। इसी दिन को प्रत्येक वर्ष राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके पश्चात भी एकीकरण की प्रक्रिया जारी रही और वर्तमान स्वरूप में राजस्थान अंततः 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया। यह राजस्थान के पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों का परिणाम था।

राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियां भी अलग–अलग क्षेत्र में अलग–अलग थीं। जयपुर के आसपास क्षेत्र में ढूंढाड़ी, अजमेर क्षेत्र में मेरवाड़ा, भरतपुर क्षेत्र में ब्रज, जोधपुर क्षेत्र में मारवाड़ी, सीकर–झुंझुनू–चूरू में शेखावाटी, उदयपुर क्षेत्र में मेवाड़ी, सिरोही–जालौर क्षेत्र में गोड़वाड़ी, डूंगरपुर–बांसवाड़ा में वागड़ी, गंगानगर एवं उसके आसपास के क्षेत्र में पंजाबी बोली जाती थी। इस प्रकार राजस्थान का निर्माण तो हो गया किंतु अलग–अलग क्षेत्र की बोलियों, खान–पान, रहन–सहन में काफी अंतर था। यह अंतर आज भी देखा जा सकता है।

राजस्थान, भारत के सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है जिसका क्षेत्रफल 342239 वर्ग किलोमीटर है जो भारत के कुल क्षेत्रफ़ल का 10.4 प्रतिशत है। राज्य का बहुत बड़ा भू–भाग थार मरुस्थल का हिस्सा है। राजस्थान की सीमा पांच राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश और गुजरात से लगती है। राज्य की पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा लगभग 1200 किलोमीटर है, जो गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, और जैसलमेर में स्थित है। राज्य की जनसंख्या 1947 में लगभग एक करोड़ थी जो वर्तमान में लगभग आठ करोड़ है।

1956 में राज्य में 26 जिले थे, जिनकी संख्या 2023 के चुनाव से पूर्व 50 हो गई थी। अब नौ जिलों को कम करने के कारण वर्तमान में जिलों की संख्या 41 हो गई है। राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद 16 लाख करोड़ रुपए है जो देश के राज्यों में सातवें स्थान पर है। प्रति व्यक्ति जी डी पी 1.67 लाख रुपए है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगदान खनिज, पर्यटन और कृषि का है। राज्य में कई खनिज आधारित उद्योग हैं जिनमें मुख्य ज़िंक, लाइमस्टोन, जिप्सम, सिलिका आदि हैं। भारत के कुल सीमेंट उत्पादन में राजस्थान का हिस्सा लगभग 25 प्रतिशत है। ज़िंक का तो लगभग पूरा उत्पादन ही राजस्थान में होता है।

कृषि उत्पादों में गेंहू, सरसों, सोयाबीन, बाजरा, मक्का, ज्वार, धनिया, जीरा मुख्य फसलें हैं। राज्य में कृषि उत्पाद आधारित उद्योगों की प्रचुर संभावना है जिसका समुचित दोहन अब तक नहीं हुआ है। सिंचाई सुविधाओं में विस्तार होने के फलस्वरूप कृषि उत्पादन और उत्पादकता में तेजी से वृद्धि हुई है। राजस्थान राज्य का निर्माण क्योंकि विभिन्न राजे रजवाड़ों को मिलाकर हुआ है, यहां अनेक विश्व प्रसिद्ध किले, महल, हवेलियां स्थित हैं जो पर्यटकीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पुराने किलों, महलों, हवेलियों में से कई को होटल में परिवर्तित किया जा चुका है। जब हेरिटेज होटल की नई श्रेणी को बनाया गया, तो देश के कुल मान्यता प्राप्त हेरिटेज होटलों में से लगभग 80 प्रतिशत तो राजस्थान में ही थे। राज्य का शिल्प, हस्तकला, लोक कला, लोक संगीत और यहां का आतिथ्य पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण के विषय रहे हैं। राज्य में पर्यटन विकास की जितनी संभावना है, उसका अब तक बहुत सीमित मात्रा में उपयोग हुआ है।

बाड़मेर जिले में तेल की खोज ने अर्थ व्यवस्था में बड़ा योगदान किया है। भारत सरकार द्वारा वहां रिफाइनरी स्थापित होने से न केवल राज्य की आय में अच्छी वृद्धि होगी अपितु अनेक लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार भी मिलेगा। पानी की उपलब्धता में कमी, अवश्य ही अधिक पानी की खपत वाले उद्योगों की स्थापना में बाधक रही है। एक ओर जहां देश का 10.4 प्रतिशत भू–भाग तथा देश की कुल जनसंख्या का 5.6 प्रतिशत राजस्थान में है, वहीं देश में उपलब्ध कुल जल का केवल 1 प्रतिशत ही राजस्थान में है। इन सब चुनौतियों के बावजूद राजस्थान ने स्वतंत्रता के बाद विभिन्न क्षेत्रों में बहुत प्रगति की है।

राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा रहा है। 1951 में साक्षरता प्रतिशत महिलाओं का 3 प्रतिशत, पुरुषों का 15 प्रतिशत और कुल 9 प्रतिशत था। साक्षरता अभियान के प्रभावी और सफल क्रियान्वयन के कारण 1991से 2001 के मध्य साक्षरता में किसी भी राज्य से अधिक वृद्धि राजस्थान में हुई । जो साक्षरता 1991 में 38 प्रतिशत थी, वह बढ़कर 2001में 61 प्रतिशत हो गई । यह सब सरकार और नागरिक संगठनों के सामूहिक प्रयास से ही संभव हो पाया। राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में अनेक नवाचारों का गढ़ रहा है, जैसे लोक जुंबिश, शिक्षा कर्मी आदि। इन सब प्रयोगों को मुख्य धारा में अपनाने से पहले ही छोड़ देने के कारण शिक्षा की गुणवत्ता में ह्रास हुआ है। राज्य में स्कूली और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संख्यात्मक विकास तो बहुत हुआ किन्तु गुणवत्ता में अब भी बहुत सुधार करने की आवश्यकता है। राज्य में वर्तमान में 1.20 लाख कुल विद्यालय हैं जिनमें से 34000 निजी क्षेत्र में हैं।

गत कुछ सालों में बहुत बड़ी संख्या में कॉलेज और विश्वविद्यालय खोल दिए गए हैं। यहां तक कि प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं और विश्विद्यालयों की संख्या भी 100 से अधिक हो गई है किंतु शिक्षकों के अधिकांश पद रिक्त होने से राज्य के विद्यार्थियों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पाई है। तेजी से औद्योगिकीकरण और विकास के लिए उपयुक्त मानव संसाधन उपलब्ध होना अत्यंत आवश्यक है। आशा है, इसके महत्व को समझते हुए इस दिशा में आवश्यक कदम सरकार उठाएगी।

राजस्थान में निवेश और रोजगार को तीव्र गति से बढ़ाने के लिए हाल ही में राज्य सरकार ने इन्वेस्ट राजस्थान नाम से बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें देश–विदेश के कई उद्योगपतियों को आमंत्रित किया गया एवं उन्हें राज्य के विभिन्न पर्यटक की संपदाओं से भी अवगत कराया गया। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से एवं फिल्म निर्माण के माध्यम से रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से आईफा का आयोजन जयपुर में हाल ही में किया गया। इसके कारण राज्य को एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुन स्थापित होने का अवसर मिला है।

राजस्थान के त्वरित विकास में और इसे अपेक्षा अपराध रहित करने में यहां के नौकरशाही एवं पुलिस की भी बहुत बड़ी भूमिका है। इस दिशा में अभी बहुत कमी है। यहां की नौकरशाही की मानसिकता अभी भी जनोन्मुखी नहीं है। इस कारण कोई भी निर्णय लेने में अत्यधिक देरी होती है और भ्रष्टाचार का बोलबाला भी होता है। यदि राज्य को अपनी प्राकृतिक और ऐतिहासिक संपदा का पूरा उपयोग आर्थिक प्रगति के लिए करना है, तो नौकरशाही को संवेदनशील और त्वरित निर्णय लेने वाला बनाना होगा। राजस्थान वर्तमान में आर्थिक समृद्धि की दृष्टि से सातवें स्थान पर है परन्तु इसमें प्रथम चार राज्यों में आने की पूरी क्षमता है। राजस्थान दिवस सरकार और नागरिकों, दोनों को आत्मावलोकन का अवसर प्रदान करता है कि हम अपने राज्य को गौरवशाली स्थान पर ले जाएं। सरकार का यह कदम स्वागत योग्य है कि वह राजस्थान दिवस पर एक दिन के औपचारिक कार्यक्रम के स्थान पर इस वर्ष पूरे सप्ताह का समारोह आयोजित कर रही है, जिसमें जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है।

आइए, हम आज से ही इस संकल्प को पूरा करने में जुट जाएं।

–राजेन्द्र भाणावत ,
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

देशनोक पुल के निर्माण में खामियां, इस वजह से हो रहे हादसे, जांच में खुलासा

यह खुलासा जिला कलेक्टर की ओर से गठित कमेटी की जांच में हुआ है, जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी

बीकानेर, (निसं)। देशनोक पुल का निर्माण तकनीकी रूप से सही नहीं हुआ था। इस वजह से अक्सर वहां हादसे हो रहे हैं। यह खुलासा जिला कलेक्टर की ओर से गठित कमेटी की जांच में हुआ है। जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी गई है, जिसमें तकनीकी जांच के लिए जयपुर से इंजीनियरों का दल भेजने की सिफारिश की गई है।

जानकारी के अनुसार बीकानेर से करीब 30 किमी दूर देशनोक पुल पर पिछले दिनों एक ट्रोला कार के ऊपर पलट गया था। इस दुर्घटना में कार में सवार छह लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद जिला कलेक्टर ने अतिरिक्त कलेक्टर प्रशासन की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की थी। इस कमेटी ने घटना स्थल का मुआयना किया और रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप दी।

जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने बताया कि रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी गई है। पुल का निर्माण तकनीकी रूप से सही नहीं बताया गया है। इसकी जांच के लिए जयपुर से इंजीनियरों का दल भेजने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में पुल में सुधार करने के भी सुझाव दिए गए हैं।

दरअसल कमेटी में आरटीओ, पुलिस, पीडब्ल्यूडी की नेशनल हाइवे विंग के एसई और नागौर एक्सईएन, टोल कंपनी और पुल निर्माण कंपनी के प्रतिनिधियों के अलावा एक्सपर्ट के तौर पर एनएचएआई के परियोजना निदेशक पीयूष रंजन यदुवंशी भी शामिल किया गया था। सभी ने अपनी–अपनी राय दी है। हालांकि कमेटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। इसलिए इसे गोपनीय रखा गया है।

> ■ **जांच रिपोर्ट में तकनीकी जांच के लिए जयपुर से इंजीनियरों का दल भेजने की सिफारिश की गई है**

रिपोर्ट में मोटे तौर पर रोड इंजीनियरिंग को सुधारने पर जोर दिया गया है। इस संबंध में एक्सपर्ट इंजीनियर से भी राय ली तो उन्होंने भी पुल तकनीकी आधार पर गलत बताया है। कलेक्टर की रिपोर्ट को ही अधिकृत माना जाएगा। देशनोक पुल का स्लॉप ज्यादा है। टू लेन पुल में एस कर्व देना ही गलत है। उस पर ओवरटेक की अनुमति नहीं होने का बोर्ड भी नहीं लगा है। गर्मी में यहां का तापमान 50 डिग्री तक जाता है, जिससे डामर पिघल कर इकट्ठा हो जाता है। इससे भारी वाहनों का संतुलन अक्सर बिगड़ता है। ऐसे में पुल की समय–समय पर मरम्मत होती रहनी चाहिए। सेंटर लाइन कंटीन्यू होनी चाहिए। यह इस बात का संकेत होता है कि ओवरटेक ना करें, जबकि पुल पर सेंटर लाइन डॉटेड है। पलाना पुल पर भी ऐसी ही स्थिति है। नागरिक सूचना बोर्ड ही गायब है। 30 लाख से अधिक के काम में नागरिक सूचना बोर्ड डिस्प्ले करना पड़ता है, जिस पर निर्माण एजेंसी का नाम, लागत, गारंटी पीरियड, जिम्मेदार अधिकारी, एक्सईएन और एईएन के मोबाइल नंबर आदि होने चाहिए, जो आजकल नहीं होते। बीकानेर से नागौर तक करीब 108 किलोमीटर रोड टू लेन की जगह फोर लेन बनाई जाएगी। इस मार्ग पर पलाना, देशनोक, नोखा और नागौर पर चारों पुल भी फोर लेन या सिक्स लेन किए जाएंगे।

नेशनल हाइवे नागौर के एक्सईएन दीपक पड़िहार ने बताया कि मार्ग को रि–डिजाइन करने के लिए 91 लाख की डीपीआर के टेंडर हो चुके हैं। एक कंपनी को वर्क ऑर्डर दिया जाना है। कंपनी की सर्वे रिपोर्ट से पता चलेगा कि इस मार्ग पर ट्रैफिक लोड़ कितना बढ़ा है और आने वाले 25 साल में कितना बढ़ेगा। उसके आधार पर इसे फोर लेन और ओवर ब्रिज फोर लेन या सिक्स लेन किए जाएंगे। गौरतलब है कि इस मार्ग का निर्माण कार्य 2022 में पूरा हुआ था। इस पर 370 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। डीपीआर 2013–14 में बनाई गई थी। रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर पुल बनाए गए।

शिक्षक को बकाया वेतन नहीं दिया तो संयुक्त निदेशक का वेतन रोका

बीकानेर, (निसं)। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने शिक्षा विभाग के चूरू मंडल के संयुक्त निदेशक के वेतन रोकने के आदेश दिए हैं। दरअसल, अदालती आदेश के बाद भी एक शिक्षक को बकाया वेतन भुगतान नहीं करने पर हाईकोर्ट ने ये आदेश दिए हैं।

मामले के अनुसार बीकानेर में वर्तमान में लेक्चरर के रूप में काम करने वाले दिनेश मेघवाल को वर्ष 1997 में नियुक्ति मिली थी। दिनेश को जून माह में वेतन मिला था लेकिन इस महीने का भुगतान नहीं किया गया। दिनेश ने इस मामले में ट्रिब्यूनल में शिकायत दर्ज कराई। वर्ष 2020 में ट्रिब्यूनल ने वेतन देने के आदेश दिए। इसके बाद भी शिक्षा

> ■ **हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के चूरू मंडल के संयुक्त निदेशक के वेतन रोकने के आदेश दिए**

विभाग ने भुगतान करने में आनाकानी की। इसके बाद हाईकोर्ट में अपील की गई। फिर भी शिक्षक को बकाया भुगतान नहीं किया गया। परिवादी के वकील परमेंद्र बोहरा ने अदालत की अवमानना का मामला भी दायर किया। इसके बाद शिक्षा विभाग ने जनवरी में वेतन आदेश तो किए लेकिन अब तक भुगतान नहीं हुआ। बोहरा ने अदालत से इस आशय की शिकायत की तो न्यायाधीश ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से पूछताछ की। विभाग ने एक महीने के भीतर भुगतान करने का विश्वास दिलाया। इस पर न्यायाधीश ने चूरू के संयुक्त निदेशक का वेतन रोकने का आदेश दिया। अधिवक्ता बोहरा ने बताया कि कर्मचारी को समय पर वेतन नहीं देने पर न्यायालय ने सख्ती दिखाई है।

ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम में ऊर्जा बचाने का संदेश दिया

सीकर, (निसं)। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड जिला मुख्यालय सीकर के निर्देशन में स्थानीय संघ शिवसिंहपुरा के तत्वावधान में सोमवार को विद्यालय कुशालपुरा में ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय संघ उप प्रधान बीरबल सिंह मूंड की अध्यक्षता एवं मुख्य अतिथि राजेंद्र प्रसाद मील सहायक जिला कमिश्नर स्थानीय संघ के सानिध्य में किया गया। कार्यक्रम में ऊर्जा बचाने का संदेश दिया गया।

कार्यक्रम में सरोज लॉयल, बसंत कुमार लाटा सी.ओ.स्काउट सीकर, राकेश बड़ौदा सरपंच कुशलपुरा, शारदा प्रधानाचार्य महात्मा गांधी गुंगारा, जवाहर सिंह सेवानिवृत्ति व्याख्याता, पुरुषोत्तम सोनी जिला प्रशिक्षण आयुक्त ,रामचंद्र सिंह आर्य समाजसेवी ने अपने–अपने विचारों के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण के बारे में प्रोत्साहित किया।

कार्यक्रम में ऊर्जा संरक्षण चेतना रैली के साथ–साथ निबंध, रंगोली, क्विज, पोस्टर, भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण का संदेश जन–जन में पहुंचने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम का संचालन महेंद्र कुमार पारीक द्वारा किया गया।

कार्यक्रम में कमलेश कुमार शर्मा, विजय कुमार शर्मा निदेशक श्री श्याम पब्लिक स्कूल, प्रेम सिंह नेहरा, बनवारी लाल, अलिताब धोबी, सौरभ जांगिड़, राधेश्याम शर्मा, आदिल खान, सुभाष चंद्र, मोहम्मद इरफान, जयचंद शुक्ला, कुलदीप, खेमराज, रचना पूनिया, राजकुमार, रामपाल सिंह, संजू उपस्थित रहे।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

शनिवार 29 मार्च, 2025

चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, अमावस्या, शनिवार, विक्रम संवत 2081, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र सायं 7:27 तक, ब्रह्म योग रात्रि 10:03 तक, नाग करण सायं 4:28 तक, चन्द्रमा मीन राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य–मीन, चन्द्रमा–मीन, मंगल–मिथुन, बुध–मीन, गुरू–वृष, शुक्र–मीन, शनि–कुम्भ, राहु–मीन, केतु–कन्या राशि में।

आज चैत्री शनिश्चरी अमावस्या, देव पितृकार्य अमावस्या, मन्वादि, पंचक है। आज शनि मीन राशि में रात्रि 9:47 पर प्रवेश करेगा। चान्द संवत्सर 2081 विक्रम सम्वत समाप्त होगा।

श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ 7:57 से 9:28 तक, चर 12:32 से 2:03 तक, लाभ–अमृत 2:03 से 5:07 तक।

राहूकाल: 9:00 से 10:30 तक। सूर्योदय 6:25, सूर्यास्त 6:39

मेष
घर–गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण परेशानी हो सकती है। मन में असंतोष बना रहेगा।

वृष
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।

मिथुन
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। व्यावसायिक यात्रा संभव है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी।

कर्क
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक खर्चों पर नियंत्रण रखें।

सिंह
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। व्यावसायिक परेशानियां अभी बनी रहेगी।

कन्या
परिवार में आपसी सहयोग–समन्वय बना रहेगा। परिवार में वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे।

तुला
व्यावसायिक कार्यों से संबंधित विवादों से राहत मिल सकती है। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

वृश्चिक
परिवार में धार्मिक–सामाजिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिजनों से उचित सहयोग मिलेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु
घर–परिवार में आपसी अनबन–मतभेद हो सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मकर
व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। आज अटका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

कुंभ
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच–विचार हो सकता है। परिवार में सुख–सुविधाएं बढ़ेगी।

मीन
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मन:स्थिति में सुधार होगा। मनोबल–आत्मविश्वास बढ़ेगा। व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।